

यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लिए 17 एमओयू, 4500 करोड़ का निवेश

अमर उजाला ब्यूरो

रक्षामंत्री व सीडीएस की मौजूदगी में हुए समझौते

लखनऊ। एयरो इंडिया-2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरल विपिन रावत की मौजूदगी में यूपीडा व निवेशकों के बीच 17 एमओयू किए गए। इससे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में करीब 4,500 करोड़ रुपये का निवेश हो सकेगा।

बंगलूरु में आयोजित एयरो इंडिया-2021 में यूपीडा ने भी भाग लिया। शुक्रवार को वहां यूपीडा के साथ इंडियन एयर फोर्स, एचएएल, नैनी एयरोस्पेस, बीईएमएल, नड्रोडाइनामिक्स, कल्याणी स्ट्रेटिजिक सिस्टम, माहेश्वरी वायर्स, रॉयल सेल्स, डातुम कंपोजिट्स, अंशु मेटल्स, ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेक्यू, पीटीसी व सारू स्मेल्टिंग ने एक-एक तथा एसएमसीपी ने तीन एमओयू साइन किए। बताया गया कि यूपीडा की ओर से एमओयू दस्तावेज पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा अरुनीता कुमार अवस्थी ने हस्ताक्षर कर भेजा था। यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीश चंद्र वर्मा ने वहां कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ एमओयू का आदान-प्रदान किया। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रक्षा उत्पादों से जुड़ी इकाइयों की स्थापना से बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हो सकेगा।



स्टार्टअप मंथन को संबोधित करते रक्षामंत्री राजनाथ सिंह।

2025 तक 25 अरब के घरेलू रक्षा उत्पादन और 5 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य

बेलाहाका एयर फोर्स स्टेशन पर आयोजित बंधन कार्यक्रम में रक्षामंत्री ने कहा कि हमें 2025 तक 25 अरब डॉलर के घरेलू रक्षा उत्पादन और 5 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है। इसमें एयरोस्पेस क्षेत्र की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-20 में रक्षा निर्यात 2000 करोड़ से बढ़कर 9000 करोड़ रुपये हो गया। इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि हमारे रक्षा निर्यात का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र से है।

2022 तक रक्षा आयात 14.56 हजार करोड़ करेंगे

बंगलूरु। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा, रक्षा से संबंधित वस्तुओं के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 2022 तक रक्षा आयात को 2 अरब डॉलर (करीब 14.56 हजार करोड़ रुपये) तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत की सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए रक्षा उपकरणों के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता अति आवश्यक है। इस मकसद में स्टार्टअप अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आईडेक्स (रक्षा उत्कृष्टता के लिए इन्वेंशन) पहल सबसे प्रभावी और बेहतरीन ढंग से क्रियान्वित रक्षा स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। उन्होंने अधिकारियों से आईडेक्स के तहत आने वाले स्टार्टअप का अनुदान बढ़ाने को कहा।

रक्षामंत्री ने कहा, दिसंबर 2020 में सरकार द्वारा दिए गए 48,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 83 एलसीए वेजस एम्के-1ए का ऑर्डर घरेलू रक्षा विनिर्माण, विशेष रूप से एयरोस्पेस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। 2016 और 2019 में घरेलू विनिर्माण

के लिए 37 अरब डॉलर से अधिक के 138 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने सीडीएस जनरल विपिन रावत से बात की और उन्होंने भी आईडेक्स के तहत स्टार्टअप को मिलने वाली राशि को कम बताने हुए चिंता जताई। रक्षा उत्पादन सचिव और रक्षा सचिव को इस राशि में बदौलती करने को कहा है।

एयरो इंडिया-2021 में 'स्टार्टअप मंथन' में उन्होंने कहा कि आईडेक्स आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने को दिशा में निर्णायक कदम है। आईडेक्स को अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में हमने निजी उद्योग के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि फंड योजना के जरिये 3.84 स्टार्टअप में 4500 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इस से भी 45 एमएसएमई ने हिस्सा लिया जिन्हें 203 करोड़ रुपये के आर्डर मिले हैं। इस से के दौरान 128 एमओयू, 19 टीओटी, 4 हार्डिंग ओवर्स, 18 उत्पाद लॉन्च किए गए और 32 अहम पोषणएं की गईं। एजेंसी